ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
© IJMRAST \ Vol. I \ Issue I \ August 2023
Available online at: www.ijmrast.com

भारतीय उच्च शिक्षा के उभरते प्रश्न

दीसी गुप्ता

सहायक आचार्य हिन्दी, रूपरानी महिला महाविद्यालय, भगहर बुलंद, गोंडा, उत्तर प्रदेश, भारत

ईमेल: deeptig1184@rediffmail.com

सारांश:

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था के ज्वलंत मुद्दों को बड़ी पारदर्शी तरीके से सामने लाने का प्रयास किया गया है| शिक्षा व्यवस्था में हो रहे अवमूल्यन से समाज के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यह शोध पत्र प्रस्तुत है।

मूल शब्द: भारतीय उच्च शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, तकनीकी, विकास

भारतीय उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य वास्तव में बड़ा भयावह और सोचनीय है | विकसित देशों में 17 से 24 वर्ष के आयुवर्ग के लगभग 55% युवा उच्च शिक्षा में नामांकित होते हैं| जबकि भारत में यह प्रतिशत मात्र 20% है | शोध और आंकड़े बताते है कि कनाडा में यह प्रतिशत 80% तक पहुंचता है | शिक्षा में सन 1985 से "उदारीकरण" शुरू हुआ, सन 1991 से इसका विस्तार हुआ, तथा "उच्च शिक्षा में संस्थाओं का विस्तार हुआ | सन 2007 में 378 विश्वविद्यालय थे इसमें 216 राज्य स्तरीय, 102 डीम्ड तथा 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालय थे, कालेजों की संख्या 18064 थी |[1] संस्थानों का विस्तार हुआ पर अभी भारत में 11% बच्चे उच्च शिक्षा में नामांकित हो पाते हैं जबकि विकसित देशों में यह प्रतिशत 54.6 है |[2]

उच्च शिक्षा में वर्ष 2007 में सकल नामांकन अनुपात -

देशों का समूह	नामांकन अनुपात (लगभग)
विकसित देश	54.6
एशियाई देश	22.6
विश्व का औसत	23.2
भारत में	11.0

इस दृष्टि से भारत की उच्च शिक्षा में नामांकन का परिदृश्य विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम है| चिंतन का विषय है कि वर्तमान सरकारी या निजी सेवाओं में उच्च शिक्षा अनिवार्य सी है यद्यपि विभिन्न शोध और आंकड़े नामांकन के प्रतिशत दिखाते हैं, फिर भी नामांकन का वर्तमान परिदृश्य काफी निराश करता है| आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर छात्र (जैसे-चायवाले, रिक्शाचालक, दैनिक मजदूर आदि) उच्च शिक्षा में नामांकित ही नहीं होते और यदि नामांकित भी होते है तो 9% शिक्षा अपूर्ण छोड़ देते हैं | "शिक्षा में निजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलने से स्ववित्तपोषित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे हैं |[3]

विद्यालयों की संख्या एवं संस्थाओं की आवश्यकताओं को बिड़ला अम्बानी रिपोर्ट 2015 में प्रक्षेपित किया गया |[4]

	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा
विद्यार्थियों की सं० अनु०	22.6 करोड़	11.3 करोड़	11.0
संस्थाओं की कुल आवश्यकता –	1506667	125556	37931
वर्तमान उपलब्धता-	775000	102000	10460

आजादी के इतने वर्षों के बाद तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के बावजूद भारत के अनेक ऐसे जनजातीय अल्पविकसित क्षेत्र है जहाँ उच्च शिक्षा नहीं पहुँची | क्षेत्रीय/भौगोलिक असंतुलन और सुदूर क्षेत्रों के थोड़ी सुविधा संपन्न छात्रों तक भी उच्च शिक्षा नहीं पहुँच पायी | पिछले 20-25 वर्षो में शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ी है, जिनमे 11% छात्र विश्वविद्यालयों में शेष 89% महाविद्यालयों में नामांकित होते हैं | शिक्षा के उपयुक्त सुविधा संसाधनों के अभाव में प्रायः ऐसे संस्थान मात्र नामांकन एवं परीक्षाकेंद्र बनकर रह जाते हैं जिसके कारण शैक्षिक गुणवत्ता तथा परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो रही है ऐसे महाविद्यालयों की संख्या नाममात्र रह गयी है, जहाँ परीक्षा पूर्ण पवित्रता के साथ सम्पादित हो रही है | डॉ० राधा कृष्णन कमीशन 1948-49 के अनुसार,- "उच्च शिक्षा में कोई एक सुधार करना हो तो वह है – "परीक्षा का सुधार"[5]

उच्च शिक्षा में परीक्षा विभिन्न कारणों से विश्वसनीय नहीं रह गयी है| प्रायः ऐसे प्रश्न-पत्र नहीं बनाये जाते जिसमें छात्रों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है | वर्तमान के प्रश्नपत्रों में प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है | प्रश्नपत्र ऐसा बनाया जाय कि परीक्षार्थी पुस्तक लेकर भी उत्तर न खोज पाने के कारण नक़ल न कर सकें, और समग्र पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए बाध्य हो जाये | शिक्षक न तो बृहद पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर पढ़ाते हैं और न ही परीक्षा लेते हैं | पाठ्यक्रम पर विचार करें तो कहा जाता है कि वर्तमान पाठ्यक्रम समय-पश्च (पुराने)हो गए हैं और इनमें नवीनता का अभाव है | किन्तु जो पाठ्यक्रम हैं वे ही सम्यक रूप से पढ़ाए नहीं जाते| कुछ विश्वविद्यालयों में अध्यापक समय-समय पर अपने पाठ्यक्रमों में नए-नए अध्यायों को जोड़ते चलते हैं | यह उत्कृष्ट प्रवृत्ति वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य को अधिक स्तरीय बना सकती है | शिक्षा में निजीकरण से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कम किन्तु आर्थिक लाभ अधिक हो रहें है| निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अधिकतर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में रूचि लेते हैं | बड़े – बड़े लुभावने,कर्णप्रिय, और मनमोहक विज्ञापनों से युवा छात्रों आकर्षित करते हैं ऐसे निजी संस्थानों में पैसे का खेल अधिक होता है| प्रायः अर्थ संपन्न और उच्च मध्यम वर्ग के ही युवा इनमें प्रवेश पाते हैं जबकि अर्थाभाव के कारण अधिकांश योग्य छात्र प्रवेश नहीं पाते | "शैक्षिक विकास मुख्यतः माध्यमिक एवं उच्च स्तरों पर निर्धनों की अपेक्षा संपत्तिशालियों को अधिक लाभान्वित करता रहा है |"[6]

जो आर्थिक रूप से संपन्न है ऐसे युवा अच्छी शिक्षा खरीद पाते हैं, अर्थ विहीन छात्र सुविधा विहीन महाविद्यालयों में शिक्षा पाते हैं इससे अमीरी गरीबी की खायी बढती जाती है|

उपभोक्तावाद और बाजारीकरण का सर्वाधिक व्यापक प्रभाव उच्च शिक्षा पर पड़ा है जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों की बाढ़ सी दिखाई देती है विद्यार्थी और अभिभावक यह समझतें हैं कि कोचिंग ही शिक्षा – नौका को पार लगा सकती है, इस भ्रमपूर्ण मानसिकता को विकसित करने में बाजारीकरण और उपभोक्तावाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है| ऐसे कोचिंग संस्थानों में शिक्षा का क्रय – विक्रय होता है यहाँ भी अर्थसंपन्न छात्र के अभिभावक प्रति वर्ष 3-4 लाख खर्च करते हैं जबकि सामान्य छात्र अभावों में जूझता रहता है| कम्प्यूटर और इन्टरनेट के बढ़ते प्रयोग ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को खासा प्रभावित किया है| यह सुविधाएँ भी जरूरतमंद विद्यार्थियों तक सुलभ नहीं है| उच्च शिक्षा में आने वाले अधिकांश फेसबुक, इन्टरनेट, चैटिंग अदि के प्रयोग में भ्रमित हो रहें हैं| इन्टरनेट

पर सभी बातें शिक्षोपयोगी नहीं हैं | अनेक प्रकरण छात्र के समय को व्यर्थ करते हैं | चैटिंग अदि का व्यसन होने पर विद्यार्थी अपने मूल शैक्षिक उद्देश्यों से भटक जाते हैं|

जिससे उनकी शैक्षिक दक्षता और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है | अतः उच्च शिक्षा का यह दायित्व बढ़ जाता है कि वह विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति ईमानदार, तटस्थ, मेहनती और एकाग्रचित बनाये| उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में अवकाश और कार्य दिवसों पर भी विचार होना चाहिए | तीज त्यौहार, विभिन्नजन्मदिवस तथा पुण्यतिथियाँ, चुनाव रैली और आकस्मिक घटनाओं के कारण शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाते हैं | "कार्य दिवस निश्चित होने पर भी अनेक बहानों से कार्य प्रभावित होता है | इसमें सबसे अधिक प्रभावी किसी कि मृत्यु पर शोक सभा कर विद्यालय बंद कर देना है | शोक सभा की जानी चाहिए पर छुट्टी का रिवाज ख़त्म किया जा सकता है |[7]

भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने भी एक वार्ता में कहा था कि जिस दिन मैं न रहूँ उस दिन मेरे राष्ट्र के लिए मेरे देश के नागरिक कुछ ज्यादा घंटे काम करें |

एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सत्र 60 – 70 कार्य दिवसो तक सिमट गया था | कक्षाएं न चलने के कारण शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक परिवेश नहीं निर्मित हो पाता जिससे शैक्षिक गुणवत्ता एवं स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है| ऐसे शिक्षण संस्थानों के छात्र मात्र नामांकित होकर महानगरों में आजीविका तलाशते हैं | परीक्षा के समय नक़ल करके परीक्षा देते हैं और डिग्री अर्जित करते हैं | इस प्रकार डिग्री अर्जित करने से शैक्षिक गुणवत्ता एवं स्तरीयता में उन्नति नहीं कि जा सकती |

उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कार्य पद्वति में पर्याप्त शिथिलता दिखती है | एक ओर रुड़की तकनीकी विश्वविद्यालय में लैब और पुस्तकालय देर रात तक खुले रहते हैं, दूसरी ओर ऐसे संसथान हैं जहाँ सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं और जहाँ सुविधाएँ उपलब्ध भी हैं वहां उनका समुचित उपयोग नहीं होता | "गुणवत्ता और श्रेष्ठता का प्रश्न भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की तरह उच्च शिक्षा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, केवल 50% विश्वविद्यालयों का नियम 12 B के तहत निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता के लिए तथा 40% का NAAC द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के विस्तृत सूचकों के तहत आंकलन किया गया है | UGC ने अब तक केवल 9 विश्वविध्यालयों और 97 कालेजों को श्रेष्ठता की दृष्टि से सक्षम पाया है | इसके अतिरिक्त 477 विभाग और केंद्र को श्रेष्ठता की दृष्टि से सक्षम माना है |"[8]

यदि हम वर्तमान प्रमाणों के आधार पर बात करें तो बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय NAAC के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते | इसलिए इन संस्थानों की भौतिक एवं शैक्षिक आधारभूत संरचना में तत्काल सुधार की आवश्यकता है | दुसरे शब्दों में कालेजों एवं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का पुनरुत्थान समय की मांग है|[9]

ऐसे तथ्य वर्तमान उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को उजागर करते हैं | भारत निरंतर विश्व – गुरु होने का दावा करता है जबकि विश्व के 100 विश्वविधालयों में भारत के एक भी विश्वविध्यालय का नाम नहीं आता | जिस गुणवत्ता की मांग अर्थव्यवस्था कर रही है उसकी आपूर्ति शिक्षा नहीं कर पाती | अनेक पद कुशल गुणवत्ता - युक्त जन - शक्ति के अभाव में खाली रह जाते हैं |शिक्षा बाह्य रूप में तभी कुशल मानी जाएगी जब वह गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों स्तर पर अर्थव्यस्था के लिए आवश्यक जन – शक्ति पैदा कर सकें[10]

भारतीय विश्वविध्यालयों में शिक्षित 47% युवा बेरोजगार हैं क्योंकि रोजगार प्रदायी संस्थान OUT RIGHT REJECT कर देते हैं | कारण है गुणवत्ता पूर्ण स्तरीय शिक्षा का अभाव | भारत में शिक्षित बेरोजगारों कि संख्या अधिक है शिक्षा उस प्रकार के शिक्षित कम तैयार कर रही है जो रोजगार पा सकें |[11]

परिणामतः भारत शिक्षित युवा बेरोजगारी और असंतोष जैसी ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है | अब प्रश्न उठता है कि ऐसी समस्याओं से उभरने के लिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बढाई जाये ?

वित्तविहीन महाविद्यालयों के बढ़ते क्रम में अध्यापकों का कोई वेतन क्रम लागू नहीं है, जिससे अध्यापकों कि कर्मठता पर प्रभाव पड़ता है | भारत में स्ववित्त पोषित विद्यालय , महाविद्यालयों कि स्थिति इसका एक उदाहरण है आधुनिक आवश्यकताएं इतनी बढ़ गयी हैं कि अध्यापक बहुत थोड़े वेतन पर निर्वाह नहीं कर सकता | गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए, अध्यापकों कर्मचारियों को समुचित वेतन देने की व्यवस्था करनी होगी |[12]

उच्च शिक्षा संस्थानों में योग्य एवं सक्षम शिक्षकों की कमी है | प्रायः विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 20 – 25% पद रिक्त हैं | योग्य अध्यापकों की कर्त्तव्य – निष्ठा तथा तन्मयता पूर्ण शिक्षण कार्य के द्वारा ही उच्च शिक्षा का कल्याण होगा | शिक्षकों के लिए सतत् प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता विकास के लिए कानून बनाये जाये |[13]

निजी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भरमार होती है किन्तु साहित्यिक पाठ्यक्रमों के प्रति उदासीनता स्पष्ट दिखती है ऐसे पाठ्यक्रम अप्रसांगिक हैं | ऐसा कहकर साहित्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (जैसे – कार्यालयीय हिंदी, अनुवाद विज्ञान, पत्रकारिता प्रशिक्षण और दृश्य श्रव्य माध्यम विज्ञान आदि) को जोड़ा गया और साहित्य को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़कर आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है | किन्तु वर्तमान परिदृश्य में यह ज्यादा लाभप्रद न होने के कारण लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि अनुवाद विज्ञान तथा कार्यालयीय हिंदी अदि पाठ्यक्रमों के अध्ययनोपरांत छात्रों को नौकरी नहीं मिली | जिससे छात्रों का इन पाठ्यक्रमों के प्रति झुकाव कम हो रहा है | आज कौशल विकास की बात की जा रही है जो लोग पहले से कार्य कुशल हैं उन्हें उचित अवसर नहीं मिल रहा है दूसरी ओर नए प्रशिक्षुकों को रोजगार न मिला तो इनका भविष्य क्या होगा ? जैसे B.ed, B.tech, IIT, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि | व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नाम छात्र ही व्यावसायिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं |

निष्कर्ष:

समग्रता से विचार करने पर स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा संस्थान गुणवत्ता के सूर्य न होकर मात्र दीपक रह गए हैं | ऐसे विभिन्न प्रश्न है जो उच्च शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं जैसे – रैंगिग , छात्र अनुसाशन में बढ़ता राजनीतिक हस्ताक्षेप, गुटबंदी, शिक्षा माफिया, शिक्षक हड़ताल, शिक्षक – छात्र संबंधों में अवमूल्यन, शिक्षा के प्रति घटती आस्था और रूचि आदि ऐसे प्रश्न है जिन पर समय – समय पर हमें मिलकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है | मैं समझती हूँ कि हम इस विचार विमर्श से उच्च शिक्षा के उभरते प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे|

संदर्भ सूची:

[1]. 11TH Five year Plan – Planning Commission VOL-2 Page 5

[2]. डॉ० सूर्यपाल सिंह-शिक्षा का अर्थशास्त्र, पृष्ठ -33

[3]. बिड़ला अम्बानी रिपोर्ट 2000

[4]. योजना सितम्बर 2002 पृष्ठ -22

[5]. डॉ० राधा कृष्णन कमीशन 1948-49

[6]. J.P.NAIK-Educational Planning in India Page-22

[7]. डॉ० सूर्यपाल सिंह – शिक्षा का अर्थशास्त्र, पृष्ठ -143

[8]. योजना, मई 2007 पृष्ठ -19

[9]. योजना, मई 2007 पृष्ठ -19

[10]. डॉ० सूर्यपाल सिंह - शिक्षा का अर्थशास्त्र, पृष्ठ -5

[11]. डॉ० सूर्यपाल सिंह - शिक्षा का अर्थशास्त्र, पृष्ठ -14

[12].डॉ० सूर्यपाल सिंह - शिक्षा का अर्थशास्त्र, पृष्ठ -27

[13].डॉ० सूर्यपाल सिंह - शिक्षा का अर्थशास्त्र, पृष्ठ -67.

Cite this Article:

*Deepti, "Bhaarateey Uchch Shiksha Ke Ubharate Prashn", **International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST)**, ISSN: 2584-0231, Volume 1, Issue 1, pp. 08-12, August 2023. **Journal URL:** https://ijmrast.com/*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.